भारत-अमेरिका व्यापार समझौता करीब

अमेरिकी उप विदेश मंत्री का दावा—सिर्फ एक आखिरी बाधा बाकी, जल्द मिल सकती है खुशखबरी

नई दिल्ली, 6 मई भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं. अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के 'बहुत करीब' हैं और जल्द ही इस दिशा में बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है.

हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि अभी एक 'आखिरी बाधा' को पार करना बाकी है, लेकिन उस बाधा की प्रकृति या समयसीमा के बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.

मैरीलैंड में आयोजित सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान पत्रकारों से बातचीत में लैंडो ने भारत को दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक क्षमता काफी व्यापक है और आने वाले वर्षों में यह तेजी से उभरकर सामने आएगी.

इस प्रस्तावित व्यापार समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. इससे पहले 2 फरवरी को भारत और अमेरिका ने इस समझौते का प्रारंभिक ढांचा तैयार किया था, जिसके बाद से लगातार बातचीत जारी है.

> विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. विशेषकर प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी.

रुपया दबाव में-डॉलर के मुकाबले 95 पर रह सकता है

नई दिल्ली, 6 मई. अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय रुपये पर दबाव बना हुआ है. फिच समूह की कंपनीने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2026 के अंत तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 95 रुपये के स्तर पर रह सकता है. वर्तमान में भारतीय मुद्रा 95.20 रुपये प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रही है.रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान रुपया करीब चार प्रतिशत कमजोर हुआ.इसका मुख्य कारण उभरते बाजारों में निवेशकों की अनिश्चितता और भारत की ऊर्जा आयात पर उच्च निर्भरता है. वित्त वर्ष 2025-26 में कुल आयात का 22 प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा आयात का था.

दो दिन में 87 लाख सिलेंडर सप्लाई

पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति सामान्य

88 .82 लाख सिलेंडरों की हुई बुकिंग

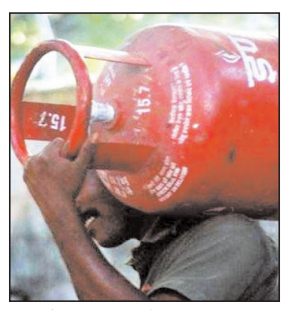

नई दिल्ली, 6 मई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देशभर में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर बड़ा अपडेट जारी करते हुए बताया है कि पिछले दो दिनों में 87.28 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। यह आंकड़ा उस समय सामने आया है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने साफ किया है कि भारत में रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, इसी अवधि में करीब 88.82 लाख सिलेंडरों की बुकिंग दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। खास बात यह रही कि लगभग 95 प्रतिशत सिलेंडरों की डिलीवरी उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के आधार पर की गई। इस नई प्रणाली का उद्देश्य वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और कालाबाजारी या गड़बड़ी को रोकना है।

> मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। देशभर के पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और घबराकर अतिरिक्त खरीदारी न करें। केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखते हुए सामान्य तरीके से ईंधन और गैस का उपयोग करें, ताकि सप्लाई व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

चांदी उछली, सोना भी हुआ महंगा

5800 रुपए चढ़ी चांदी

800 रुपए महंगा हुआ सोना

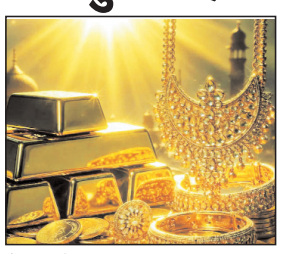

नई दिल्ली, 6 मई भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली. खासतौर पर चांदी के दाम में बड़ा उछाल दर्ज किया गया, जहां कीमतों में करीब 5800 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई. वहीं सोना भी महंगा हुआ, जिससे आम खरीदारों और निवेशकों दोनों पर असर पड़ा है.

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, चांदी की कीमतों में तेज उछाल के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और डॉलर की कमजोरी मुख्य वजह मानी जा रही है. इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी कीमती धातुओं को सहारा दिया है. सोने की बात करें तो 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों ही श्रेणियों में कीमतों में 600 से 800 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे बाजार में फिर से रौनक लौट आई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोना और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं.

एनबीसीसी ने आईआईएफटी परिसर नींव रखी

लगभग 54,000 वर्गमीटर के कुल निर्मित क्षेत्रफल के साथ 7 .55 एकड़ के भूखंड पर विकास कार्य

नई दिल्ली, 6 मई आने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 5 मई, 2026 को मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए परिसर की आधारशिला रखी.

डिज़ाइन, इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण के आधार पर निष्पादित की जा रही इस परियोजना की संस्वीकृत लागत लगभग 350 करोड़ रुपये है. डॉ. के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी लिमिटेड ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की.इस समारोह में डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) के साथ-साथ वरिष्ठ गण्यमान्य व्यक्ति, संस्थागत हितधारक और एनबीसीसी के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे. इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. महादेवास्वामी ने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना केवल आईआईएफटी के भौतिक विस्तार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और संस्था की सहयोग करने की क्षमता में एक दीर्घकालिक निवेश है. दक्षिण दिल्ली में 7.55 एकड़ भूमि पर आईआईएफटी का नया परिसर विकसित किया जा रहा हैजो मेट्रो स्टेशनों, प्रमुख सड़क नेटवर्क्स और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित शहर के प्रमुख हिस्सों से उत्कृष्ट रूप से जुड़े होने के साथ-साथ कार्यनीतिक रूप से छतरपुर के निकट स्थित है.

> आधुनिक और एकीकृत शैक्षणिक केंद्र के रूप में परिकल्पित, इस परिसर का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 54,000 वर्ग मीटर होगा, जिसे संस्थान के मौजूदा परिसर की क्षमताओं को पूरक एवं विस्तारित करने हेतु डिजाइन किया गया है .इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा समग्र वातावरण प्रदान करना है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान नवोन्मेष और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे. परिसर को अत्याधुनिक शैक्षणिक, आवासीय और संस्थागत सुविधाओं को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है .प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने हेतु शैक्षणिक ब्लॉक में स्मार्ट क्लासरूम, व्याख्यान हॉल, संकाय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष तथा एक आधुनिक लाइब्रेरी होगी.

यूआईडीएआई एनएफएसयू संग साइबर सुरक्षा समझौता

नई दिल्ली, 6 मई 2026 भारत के डिजिटल ढांचे को और सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ पांच वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौता किया है. यह साझेदारी डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने पर केंद्रित है.

इस समझौते के तहत दोनों संस्थान मिलकर साइबर सुरक्षा ऑडिट, फोरेंसिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण जैसे अहम क्षेत्रों में काम करेंगे. सहयोग की रूपरेखा छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास, सूचना सुरक्षा, फोरेंसिक अवसंरचना, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और रणनीतिक प्लेसमेंट शामिल हैं. यूआईडीएआई के सीईओ विवेक चंद्र वर्मा और एनएफएसयू के निदेशक प्रोफेसर एस.ओ. जुनारे के बीच इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया. इस दौरान दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. यह पहल भारत के डिजिटल पहचान तंत्र को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.

खास बात यह है कि इस सहयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डीपफेक डिटेक्शन और क्रिप्टोग्राफी जैसी उभरती तकनीकों पर संयुक्त अनुसंधान किया जाएगा. इससे न केवल साइबर खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई मजबूती मिलेगी.

> यूआईडीएआई के अनुसार, यह साझेदारी भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

शांति वार्ता में प्रगति से शेयर बाजारों में तेजी

मुंबई, 06 मई अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति से उत्साहित निवेशकों की लिवाली से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों तेजी रही और प्रमुख सूचकांक करीब सवा प्रतिशत की बढ़त में बंद हुए.

बीएसई का सेंसेक्स 940.73 अंक (1.22 प्रतिशत) उछलकर 77,958.52 अंक पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 298.15 अंक यानी 1.24 प्रतिशत चढ़कर 24,330.95 अंक पर बंद हुआ. यह दोनों सूचकांकों का दो सप्ताह का उच्चतम स्तर है.

बाजार में चौतरफा लिवाली रही. वृहत बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.21 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.93 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ शांति वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है और इसलिए उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए शुरू किये गये 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है.

> एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में लिवाली का जोर रहा. ऑटो, वित्त, बैंकिंग, फार्मा, रियलटी और रसायन समूहों के सूचकांक दो से तीन प्रतिशत तक चढ़े. स्वास्थ्य, धातु और मीडिया समूहों के सूचकांक भी एक प्रतिशत से ज्यादा मजबूत हुए.

घरेलू मांग के दम पर अप्रैल में सेवा क्षेत्र की बढ़ी रफ्तार

मुंबई, 06 मई.पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू मांग मजबूत रहने से अप्रैल में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी देखी गयी.

एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी सूचकांक मार्च के 57.5 से बढ़कर 58.8 पर पहुंच गया जो पांच महीने का उच्चतम स्तर है. यह दिखाता है कि मार्च के मुकाबले में अप्रैल में सेवा क्षेत्र की गतिविधि न सिर्फ बढ़ी है बल्कि इसके बढ़ने की रफ्तार भी मार्च से अधिक रही.

अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक निवेश की तैयारी

नई दिल्ली, 6 मई अमेरिका में भारतीय कंपनियां 20.5 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की तैयारी कर रही हैं. यह जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी.

उन्होंने कहा कि तकनीक, विनिर्माण और औषधि जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों का निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं.सर्जियो गोर ने बताया कि एक ही दिन में 12 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1.1 अरब डॉलर के नए निवेश की घोषणा की. हालांकि, उन्होंने इन कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए.उन्होंने कहा कि ये निवेश अमेरिका में रोजगार पैदा करने और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने में मदद करेंगे.राजदूत ने इसे अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग का उदाहरण बताते हुए कहा कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र जब साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो दोनों देशों को फायदा होता है.

समाचार विशेष

सपा में बड़े बदलाव की तैयारी

संगठन में दिखेगी पीडीए की झलक

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसी के साथ समाजवादी पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई है. पार्टी अब पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को केवल नारे तक सीमित न रखकर उसे संगठन के हर स्तर पर लागू करने की रणनीति पर काम कर रही है.

महिला सभा में हालिया बदलावों के जरिए इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही अन्य फ्रंटल संगठनों और जिला इकाइयों में भी व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है. पार्टी नेतृत्व का फोकस साफ है, सामाजिक संतुलन के साथ एक ऐसा संगठन खड़ा करना जो चुनावी तौर पर अधिक प्रभावी साबित हो.

समाजवादी पार्टी ने हाल ही में महिला सभा में बड़े बदलाव करते हुए सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष और रुक्मणि देवी निषाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इन नियुक्तियों को पीडीए रणनीति को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. पहले इन पदों पर अगड़ी जाति की नेताओं का वर्चस्व था, लेकिन अब पार्टी पिछड़े और अति-पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाकर स्पष्ट राजनीतिक संदेश दे रही है.

अब फ्रंटल संगठनों में होगा व्यापक फेरबदल- सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी जल्द ही युवा सभा, छात्र सभा, मजदूर सभा, लोहिया वाहिनी, व्यापार सभा और अल्पसंख्यक सभा जैसे फ्रंटल संगठनों में भी बदलाव कर सकती है. इन संगठनों में नई जिम्मेदारियां तय करते समय सामाजिक और जातीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि संगठन के हर स्तर पर पीडीए की झलक दिखाई दे.

पार्टी केवल शीर्ष और फ्रंटल संगठनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिला और मंडल स्तर पर भी बदलाव की तैयारी चल रही है. करीब 10 से अधिक जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं. हाल ही में बरेली और बिजनौर में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति इसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है.

2027 चुनाव से पहले संगठन को धार देने की कवायद

कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अब 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को नई दिशा देने में जुटी है. सामाजिक प्रतिनिधित्व, संतुलित नेतृत्व और सक्रिय संगठन के जरिए पार्टी एक मजबूत चुनावी ढांचा तैयार करना चाहती है, जिससे आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके.

तेलंगाना रक्षाणा सेना को मिली मंजूरी

कविता की नई राजनीतिक पारी ने बढ़ाई हलचल

हैदराबाद. तेलंगाना की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है. कल्वकुंतला कविता द्वारा स्थापित नई पार्टी को आखिरकार चुनाव आयोग से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है.

पार्टी का नाम तेलंगाना रक्षा सेना तय किया गया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही नाम संक्षेप (टीआरएस) राज्य की राजनीति में पहले से एक बड़े दल से जुड़ा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है.

कविता ने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पिछले दो दशकों से तेलंगाना जागृति के जरिए जिस तरह जनता की सेवा करती रही है, उसी प्रतिबद्धता के साथ अब राजनीतिक स्तर पर लोगों की रक्षाणा और सेवा के लिए काम करेगी. उन्होंने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए यह भी कहा कि उनकी पार्टी सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी. जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2026 में पार्टी ने चुनाव आयोग को पांच संभावित नामों का प्रस्ताव भेजा था. इनमें तेलंगाना प्रजा जागृति, तेलंगाना जागृत, तेलंगाना रक्षाणा सेना, तेलंगाना राष्ट्र जागृति और तेलंगाना प्रजा शक्ति शामिल थे. चुनाव आयोग ने इनमें से तीसरे विकल्प तेलंगाना रक्षाणा सेना को मंजूरी दी है. चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि पार्टी को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, ताकि अगर किसी को नाम पर आपत्ति हो तो वह तय समय सीमा में अपनी बात रख सके.

प्रतिस्पर्धा और तेज होगी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीआरएस जैसे परिचित संक्षेप का इस्तेमाल राज्य की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकता है. एक समय में यही संक्षेप तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए पहचान बन चुका था. ऐसे में अब उसी संक्षेप के साथ नई पार्टी का आना राजनीतिक प्रतीकवाद और रणनीति दोनों के तौर पर देखा जा रहा है .कविता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हल्के अंदाज में कहा कि किस्मत में भी एक तरह का व्यंग्य होता है. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में और चर्चा को जन्म दिया है. नई पार्टी के गठन और नाम को मंजूरी मिलने के बाद यह साफ है कि तेलंगाना की राजनीति में प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है.

भाजपा का मुस्लिम प्रयोग : 277 में से 118 जीते

अहमदाबाद. गुजरात की राजनीति लंबे समय से एक तय पैटर्न पर चलती रही है, लेकिन हाल के निकाय चुनावों ने इस पैटर्न में बदलाव के संकेत दिए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट दिया, वह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है.

'सबका साथ, सबका विकास' का नारा अक्सर सुनाई देता रहा है, लेकिन इस बार Gujarat को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भाजपा की यह नई दिशा भविष्य की राजनीति का संकेत है.

क्या कहता है आंकड़ों का गणित ?- भाजपा ने इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय से 277 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जिनमें से 118 ने जीत हासिल की. यह आंकड़ा बताता है कि पार्टी को कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन 159 उम्मीदवारों की हार यह भी दर्शाती है कि यह रणनीति अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है.

क्या यह रणनीति भविष्य बदल सकती है?

भाजपा का यह प्रयोग यह संकेत देता है कि पार्टी अब पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है . मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना और उन्हें जीत दिलाने की कोशिश करना, यह दर्शाता है कि पार्टी अपने आधार को विस्तार देना चाहती है . हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि अभी इस दिशा में लंबा रास्ता तय करना बाकी है . यह रणनीति भाजपा के लिए अपने पारंपरिक वोट बैंक से बाहर निकलकर नए वर्गों को जोड़ने का प्रयास है .

विशेष राजनीतिक गलियारों में क्यों हो रही चर्चा

क्या सपा से हाथ मिलाने वाले हैं बृज भूषण?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है. वहीं चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता बृज भूषण शरण सिंह को लेकर बड़ी अटकलें सामने आ रही हैं. खबरों के अनुसार, 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बृज भूषण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं.

हालांकि अभी इसे लेकर सिर्फ संभावनाएं जताई गई हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है. बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ये खबर

ऐसे ही नहीं उठी है, बल्कि इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है. दरअसल, बृज भूषण सिंह ने अपने एक बयान में खुद कहा है कि अगर हम बोझ लगते हैं तो एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं है. उनके इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या गोंडा के बाहुबली अपनी ही पार्टी से खफा हैं और अब वह भाजपा में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया.

हालांकि इन अटकलों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हवा दी. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग भाजपा छोड़ना चाहते हैं. जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं या वहां से निकलना चाहते हैं. बात अगर पूर्व सांसद और हमारे साथ रहे गोंडा के नेता की है, तो राजनीति में क्या मोड़ आता है, यह वही बेहतर बता सकेंगे.

अभी तक नहीं किया खबरों का खंडन

हालांकि खुद बृजभूषण सिंह ने इन खबरों का कोई औपचारिक खंडन नहीं किया है, बल्कि अपने हालिया बयानों से भाजपा को नाराज कर दिया है . अखिलेश यादव के प्रति उनकी नरमी और सपा की चुप्पी ने इस चर्चा को हवा दे दी है कि आने वाले समय में गोंडा में नया सियासी ठिकाना समाजवादी पार्टी हो सकता है .